an>

Title: Need to provide reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in private industrial sector.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाये गए सतत विकास लक्ष्यों को अंगीकृत करने की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों ने अंगीकृत किया है सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 17 प्रमुख सतत लक्ष्य और 169 लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिनके अंतर्गत गरीबी को सभी रूपों में पूरे विश्व से समाप्त करना, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना, सतत कृषि को बढ़ावा देना, स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित बनाना, गुणवत्तायुक्त शिक्षा का प्रबंध करना, लैंगिक समानता प्राप्त करना, सभी के लिए जल की उपलब्धता, क्लीन ऊर्जा, सभी के स्थिर समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन इत्यादि शामिल हां भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबका साथ, सबका विकास का संकल्प लिया है। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कुशल भारत, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्ध योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा बैंक योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, स्मार्ट सिटीज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, अटल मिशन फार रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन, दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना, उज्जवला योजना, मिशन इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व नोटबंदी जैसी अनेक योजनाएं समावेशी विकास के लिए चलाई हैं, ये योजनाएं गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है।

मैं सरकार का ध्यान 1991 के पश्चात् शुरू हुए ग्लोबेलाइजेशन एंड लिबेलाइजेशन युग की उपलब्धियो की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसके अंतर्गत न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में अमीर व गरीब की खाई बढ़ी है। जैसे-जैसे निजी उद्योगों का दायरा बढ़ रहा है वैसे-वैसे देश के 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के लिए रोजगार के अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि सतत विकास को सफल बनाने के लिए निजी उद्योगों में भी अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए ताकि वे राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकें।